(3) मंत्रालय में तीन अनुभाग अर्थात् रोकड़-1, रोकड़-2 और स्थापना-4 सभी स्तरों पर अपना कार्य केवल हिन्दी में करने के लिए अभिज्ञात किए गए हैं।

(4) मंत्रालय में प्रत्येक अनुभाग को पांच ऐसी फाइलें अभिज्ञात करने के लिए कहा गया है जिनमें केवल हिन्दी में कार्य किया जा सके।

गत् वर्ष के दौरान मानीटरिंग पद्धति में हिन्दी कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी को अलग से संकलित करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि, कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए। विगत में कई कारणों से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। जिनमें प्रशिक्षित हिन्दी टाइपिस्टों की कमी और भाषा का प्रयोग करने में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त धारा-प्रवाह का अभाव शामिल है।

स्वरोजगार कार्यक्रम

92. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 288 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विधिवत स्वीकृत बहुत सी अर्जियों को बैंकों द्वारा रद्द कर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हुई है;

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं ; और एक निश्चित समय में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों को क्या अनुदेश दिए गए हैं;

(ग) जिन राज्यों में पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई उनमें आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य बढ़ाये न जाने के क्या कारण हैं ; क्या इस नीति में सुधार की कोई आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार उन बैंकों के कार्यकरण की जांच करने का विचार रखती है जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं ताकि दोषी लोगों को दण्ड दिया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

93. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कपास का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस वर्ष कपास का कैरी-ओवर (पिछला शेष) स्टाक क्या हैं और देश की आवश्यकता से यह स्टाक कितना अधिक है ;

(ग) आवश्यकता से अधिक कपास की कितनी मात्रा का और किस एजंसी के माध्यम से तथा किस-किस देश को निर्यात किया जाएगा ;

(घ) कपास की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य की घोषणा पिछली बार कब की गई थी और उनका मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इस वर्ष किसानों को कपास के लिए समर्थन मूल्य से जो कम दाम मिल रहा है ; और

(च) किसानों को कपास का लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रूई का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)